श्री खारबेल स्वाईं: महोदय मैं अपनी पार्टी का उप मुख्य सचेतक हूं। मेरा नाम क्रम में तीसरा था।*

अध्यक्ष महोदय: इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बधाई का मुझ पर असर पड़ सकता था।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, इन्होंने जो वक्तव्य दिया उसे आप कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर निकाल सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए। यदि वह अध्यक्षपीठ पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनकी टिप्पणियों पर उसी प्रकार कार्रवाई करूंगा। जिस प्रकार उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे बेहद अफसोस है। मैंने आपके पार्टी से कई सदस्यों को बोलने के लिए कहा है। मेरे सामने जो सूची है उसमें आपका नाम तीसरे क्रम पर नहीं था और आप अध्यक्षपीठ को आदेश नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: हर चीज की एक सीमा होती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। सब कुछ निकाल दीजिए। कृपया बैठ जाइए। मैंने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री से जवाब देने के लिए अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)* *

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): मैंने अपराह्न में अपना नाम दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उससे क्या होता है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको नहीं बुलाने का निर्णय लिया है। आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे अथवा नहीं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, आप चिल्लाते रहिए। बात कहने का यह तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपके कारण तब मैं सभा स्थगित कर दूंगा। यदि मैं सभा स्थगित कर दूंगा तो आपको प्रधान मंत्री के भाषण का लाभ नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं सभा भवन से बाहर जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.31 बजे

(इस समय श्री खारबेल स्वाईं सभा भवन से बाहर चले गए)

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, मैं भी एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उचित मान्यता दी जाएगी। आपको मान्यता दी गई है। आप चिन्ता न करें। सबकी यह आदत बनती जा रही है कि अध्यक्षपीठ पर ऊंगली उठाए और अध्यक्षपीठ को चुनौती दे। ऐसा करके न तो आप अपनी, न ही इस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका की मेरी यात्रा के परिणाम पर इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं विशेषकर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस चर्चा में भाग लेकर मेरा सम्मान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस स्तरीय चर्चा से हमारी सभा का मान बढ़ता है और मैं कृतज्ञ हूं कि इस सम्मानित सभा के समक्ष दिए गए मेरे वक्तव्य से उठे कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण करने के लिए मेरे पास यह अवसर है।

महोदय, 1991 के बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, संयुक्त राज्य अमेरिका की मेरी यह यात्रा एक प्रकार से बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसका सामना मैंने किया है। लेकिन पं. जवाहर लाल नेहरू जिन्होंने भारत को आज की ज्ञान शक्ति; श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने आज हमें परमाणु शक्ति और श्री राजीव गांधी जिन्होंने आज हमें सूचना प्रौद्योगिकी शान्ति बनाया है के द्वारा हमारा स्वतंत्रता के संघर्ष की शक्तिशाली विरासत से मुझे बल मिला।

आज भारत राष्ट्रों के बीच उच्च मस्तक से खड़ा है। आज हम विश्व में दूसरे सर्वाधिक विकास दर वाले देश के रूप में है। विश्व एक प्रजातंत्र के रूप में हमें आश्चर्यजनक ढंग से देखता है और सम्मान देता है। लोग इस प्रश्न को पूछते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि अरबों की जनसंख्या वाला, अनेक विविधताओं,

[डा. मनमोहन सिंह]

ऐसी विषमताओं और विश्व के सभी धर्मों वाला देश प्रजातंत्र के रूप में कैसे फल फूल रहा है। लोगों को यह भी आश्चर्य होता है कि हमारे यहां शायद हमारे नागरिकों के बीच दूसरी अथवा तीसरी सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है और फिर भी उनमें से किसी को भी अलकायदा और किसी ऐसे अन्य समूह से जुड़ा नहीं पाया गया है।

विश्व हम जो है उसके लिए सम्मान देता है। इसलिए, मेरे लिए विभिन्न गण्यमान्य व्यक्तियों राष्ट्रपति बुश से लेकर आगे के क्रम के व्यक्तियों के साथ वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में मेरे अभिभाषण एक महान विशेषाधिकार था।

महोदय, हमारी विदेश नीति के मूलभूत ढांचे के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं। हमारे देश की विदेश नीति को जब से हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने तब से हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित किया गया है, वह नीति नहीं बदली है। हमारी विश्व के प्रति अभिरुचि, बिल्कुल जैसा कि हम आज देखते हैं या जैसा हम विश्व को बनाना चाहते हैं में हमारी मजबूत सभ्यता का प्रभाव और मार्गदर्शन रहा है। जैसाकि इसे होना चाहिए, लेकिन पंडित जी कहा करते थे 'हम एक गतिशील विश्व में रहते हैं; तेजी से बदलते विश्व में रहते हैं। इसलिए, गतिशील विश्व में जटिल राजनीति के प्रबंधन में हमारे दृष्टिकोण में लचीलापन आना सम्भव है। लेकिन मूलभूत सिद्धान्तों पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

महोदय, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे इस महान उत्तरदायित्व की जानकारी थी कि मुझे कुछ ऐसा करना या कहना नहीं चाहिए जिससे हम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

महोदय, हमने इस यात्रा में जो किया उस पर दो प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं। एक प्रकार की टिप्पणियां हमारे वामपंथी साथियों ने की है उन्होंने, जिन्हें मैं बहुत सम्मान और महत्व देता हूं, कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट आने की पूर्व की सरकार की उन्हीं नीतियों को जारी रखे हुए हैं और हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में आकर डूबने का खतरा है। विपक्ष की ओर से दूसरी टिप्पणी की गई कि हमने भारत की रणनीतिक परमाणु स्वायत्तता के साथ समझौता किया है। इसलिए, मैं इन दोनों मुद्दों पर कुछ विस्तार से चर्चा करूंगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका आज महाशक्ति है, हम बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम बहुध्रुवीय विश्व का हिस्सा कैसे बन सकते हैं मैं चाहूंगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तम्भ बनने के लिए सशक्त भारत तेजी से विकसित हो। इसलिए केवल यह कहना कि हम इस बहुध्रुवीय विश्व से अलग होना चाहते हैं कोई मायने नहीं रखता। देश को मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए व्यावहारिक रणनीति पर बल देना होगा। यदि भारत अगले 10 वर्षों में आठ से दस प्रतिशत प्रतिवर्ष विकास दर से बढ़ता है तो हम शायद विश्व में तीसरी या चौथी सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और विश्व हमारा सम्मान करेगा। इसलिए, हम जानते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व है। हमारा उद्देश्य समान मानसिकता वाले देशों के साथ कार्य करके राष्ट्रों की वैश्विक परस्पर निर्भरता की समानता को लाना और उसके प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। आज के एकध्रुवीय विश्व जिसमें हम रह रहे हैं, से नहीं बचा जा सकता है। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि रातों रात हो जाए। हमें इस दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों का बहुत महत्व है। हां, ऐसा करते समय, हमें अपने राष्ट्रीय सम्मान, अपने राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, जिस विश्व में हम रहते हैं उस विश्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ना आवश्यक है। यह एक गठबंधन नहीं है। यह सैनिक गठबंधन नहीं है। किसी अन्य देश के विरुद्ध यह गठबंधन नहीं है।

जब से हमारी सरकार अस्तित्व में आई, हम ने रूस के साथ रणनीतिक भागीदारी की है। हमारे इसके साथ बहुत निकट के सम्पर्क हैं। हाल में हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी ने रूस की यात्रा की। उन्हें स्वयं राष्ट्रपति पुतिन ने काफी सम्मान दिया। कुछ माह पूर्व मैं यूरोप गया था। हमने यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ समझौता किया है। कुछ सप्ताह पहले जापान के प्रधान मंत्री यहां आए और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि उनकी यात्रा के दौरान हमारे नए संबंध बने हैं।

तत्पश्चात् हमें चीन के प्रधानमंत्री का स्वागत करने का अवसर मिला। काफी प्रयासों के पश्चात्, हमने उत्तर के अपने पड़ौसियों के साथ निकट संबंधों को प्रोत्साहित करने में सफलता प्राप्त की है। अब मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर हमने कई ऐसे समझौतों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं जिनसे भारत और चीन के बीच जटिल सीमा समस्या के समाधान का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं और मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि यह भ्रामक है। हम किसी सैनिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम किसी अन्य देश के विरुद्ध इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं कम से कम चीन के विरुद्ध तो नहीं। मैं बिल्कुल सच्चाई से यह बात कह रहा हूं। मैंने उन सार्वजनिक

चर्चाओं और प्रैस कांफ्रेंस में जिन्हें मैंने सम्बोधित किया तथा अमेरिका गण्यमान्य व्यक्तियों की बैठकों में, मैंने स्पष्ट कहा कि हम अपने महान पड़ोसी चीन के साथ कार्यरत है और भविष्य में भी जुड़े रहना चाहते हैं। हमारे आर्थिक संबंधों में विस्तार हो रहा है और मैं इस महान देश के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में नया विस्तार देख रहा हूं और यह हमारी इच्छा है कि एक साथ काम करके एशिया और यूरोप में शांति और समृद्धि की ताकतों को मजबूती मिले। अतएव, मेरी इच्छा इस मत का खंडन करने की है जिसके अनुसार हमने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ जो कुछ भी किया है वह चीन अथवा किसी अन्य देश की कीमत पर है।

हम यह मांग कर रहे हैं कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की आवश्यकता है जो हमारे विकास संबंधी प्रयासों का सहायक है। भारत की प्रमुख चिंता व्यापक निर्धनता, उपेक्षा एवं रोगों से मुक्ति पाने की है जिनसे आज भी लाखों लाख लोग प्रभावित हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कई महान कार्य किए गए हैं परन्तु निर्धनता से मुक्ति पाने की यात्रा अभी भी अपूर्ण है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर से सभी प्रयास करेंगे। आज जिस विश्व में हम रहते हैं, कोई भी देश अकेले समृद्ध नहीं हो सकता है। मुझे याद है कि पंडित नेहरु ने स्वयं कहा था और वह एक भविष्य सूचक दृष्टिकोण था। वर्ष 1947 में, उन्होंने कहा कि इस विश्व में, जिसमें हम रहते हैं, शांति, समृद्धि और कतिपय आपदा भी अविभाज्य हैं। इसलिए इस अन्तर्निर्भर विश्व में, जिसमें हम रहते हैं, हमें सहायक वातावरण की आवश्यकता है और सही या गलत, संयुक्त राज्य अमरीका उस अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को प्रभावित करता है। अतएव, मैं नहीं सोचता कि एक सम्प्रभु स्वतंत्र देश के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और गौरव के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले अमरीकी मधुर संबंधों की मांग करने में कुछ भी गलत है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने उस उत्तरदायित्व को पूरा किया है।

चर्चा किए गए अन्य विभिन्न मुद्दों के संबंध में, मैं इसके बाद बात करूंगा। परन्तु प्रमुख विपक्षी दल का मुद्दा यह है कि क्या हमने अपने नाभिकीय हथियार कार्यक्रम के प्रबंधन में अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता किया है।

इसका वर्णन करने से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका जाने से पहले मुझे विपक्ष के नेताओं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री जसवंत सिंह से मिलने का सौभाग्य मिला था। मुझे उनको यह बताने का सौभाग्य मिला था कि मैं क्या प्राप्त करना चाहूंगा। मैंने वाम दलों के अपने सहयोगियों को भी संक्षिप्त विवरण दिया। मैंने उनको उस बात का व्यापक संकेत दिया जो दांव पर लगा था। मैं परिणाम के बारे में आश्वस्त नहीं था, इसलिए मैंने सभी बातों का विवरण नहीं दिया जिन्हें बाद में संयुक्त विवरण में दर्शाया गया है। मेरी चिंता क्या थी? अपने विकास विकल्पों को व्यापकता प्रदान करने के अलावा मेरा उद्देश्य था, अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के लिए स्थान बनाना और दो विशेष कार्य करना/प्रथम, भारत के परमाणु कार्यक्रम, सामरिक कार्यक्रम के प्रबंधन में अपनी स्वायत्तता से कभी भी समझौता नहीं करना। दूसरे, परमाणु ऊर्जा मंत्री के रूप में मुझे मानना था कि, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पीछे छूट गया था। जब मैं सत्तर के दशक में सिविल सेवा में था, मैं परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य था। उस समय, परमाणु ऊर्जा आयोग ने हमारे लिए 1000 मेगावॉट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था। आज हम वर्ष 2005 में हैं। हमारी क्षमता 3,000 मेगावॉट से कम है। हमें कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ा। मैं अपने परमाणु वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने 35 वर्षों के इस नाभिकीय रंगभेद की बहुत कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत सराहनीय ढंग से कार्य किया है। परन्तु ऊर्जा सुरक्षा आने वाले वर्षों में भारत के एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारी समस्याएं हैं। कोयला पर्याप्त मात्रा में हैं। परन्तु कोयले के अधिक उपभोग से कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन जैसे पर्यावरणीय खतरे हो सकते हैं, यद्यपि स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी से इससे निपटा जा सकता है।

हम अपनी 70% आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हाइड्रोकार्बन के आयात पर निर्भर हैं। यह बहुत बड़ी निर्भरता हूं। अतएव, ऊर्जा सुरक्षा के हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हम उन विकल्पों को बढ़ाएं जो हमारे लिए खुले हैं और परमाणु ऊर्जा इनमें से एक है। यहां मैं पंडित जी के विचार के प्रति सम्मान रखता हूं। आप उस संकल्प का अवलोकन करें जिसे भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय स्वीकृत किया गया था। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हमारे लिए विद्युत उत्पादन के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह कार्यक्रम कठिनाईयों से फिर गया है। यह हमारे वैज्ञानिकों की गलती नहीं है। उन्होंने बहुत ही कठिन स्थितियों के अंतर्गत काफी अच्छा किया है। परन्तु हमें वास्तविकताओं की पहचान करनी है। अतएव, मैं यह महसूस करता हूं कि यदि हमें एक ऐसे वातावरण का सृजन करने हेतु अर्थोपायों का पता लगाना है, जिसमें पिछले 35 वर्षों में स्थापित इस प्रकार का नाभिकीय रंगभेद और प्रतिरोधात्मक प्रणालियां स्थापित की गई है, जिन्होंने हमारे उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास की दौड़ में आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को अवरुद्ध किया है, हम किस प्रकार इन निषेधात्मक प्रणालियों से मुक्ति पा सकें, तो हम ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में विकास विकल्पों को बढ़ा सकते थे। जिनकी भारत को इसकी आर्थिक और सामाजिक निर्यात को प्राप्त करने की अत्यधिक

[डा. मनमोहन सिंह]

आवश्यकता है। अतएव, अमरीका जाने से पूर्व, मैंने स्वयं से कहा कि एक तरफ हमें अपनी सामरिक संपत्ति के प्रबंधन में अपनी सामरिक स्वायत्तता को समर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ, पिछले 35 वर्षों के दौरान हमारे विकल्पों को प्रतिबंधित करने वाले इस परमाणु प्रतिबंध को दूर करने हेतु संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य मध्यस्थों का अनुसरण करने के लिए एक सम्मानीय तरीका ढूंढना चाहिए।

महोदय, मैं पूरी गंभीरता से यह कहना चाहता हूं कि हम उद्देश्यों में सफल रहे हैं। संयुक्त वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत देता हो या जिससे यह संकेत मिलना चाहिए कि हमने अपनी नाभिकीय संपत्तियों के प्रबंधन में अपनी स्वायत्तता और अपनी सम्प्रभु इच्छा-शक्ति के साथ समझौता किया है। इस विषय की कभी चर्चा नहीं की गई। मुझे वाशिंगटन में यह चिंता थी कि मैं संयुक्त राज्य अमरीका को प्रभावित करूं कि यदि संयुक्त राज्य अमरीका सचमुच यह महसूस करता है कि यदि उसने भारत के संबंध में अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, तो उसे 35 वर्षों के प्रतिबंधों, जिसके कारण नाभिकीय ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने में हमारे समक्ष बाधाएं आई हैं, को हटाने के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। परन्तु, एक प्रश्न उठाया गया है और यह प्रश्न श्री अटल जी ने उठाया है। उन्होंने कहा: "आप हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के असैनिक और परमाणु अवयवों को अलग करने जा रहे हैं। क्या आपने वैज्ञानिकों से परामर्श किया था? क्या यह व्यवहार्य है? मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं कि यही वह प्रश्न है जिस पर मेरा ध्यान काफी समय से केन्द्रित है। मैं परमाणु वैज्ञानिक नहीं हूं परन्तु मेरे पास हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों की सलाह है, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष मेरे शिष्टमंडल का हिस्सा थे। आशा है, मैं गुप्त बात को उद्घाटित नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार से, जब अमरीकी पक्ष से अंतिम प्रारूप हमें प्राप्त हुआ तो मैंने उन्हें यह स्पष्ट किया कि मैं तब तक किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा जब तक इसका समर्थन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नहीं करते। इससे हमारी वार्ता लगभग 12-15 घंटे तक रुकी रही। परन्तु अंततः, हम सफल रहे। हमारे पास एक प्रारूप था जिसको परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त था। अतएव किसी को भी यह शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश के परमाणु प्रतिष्ठान, जिन पर हमें काफी गर्व है, विचार के केन्द्र में नहीं थे।

वापस आने के बाद, मैंने कई नाभिकीय वैज्ञानिकों और अन्य वैज्ञानिकों से बातचीत की ओर मैं आश्वस्त हूं कि हमने जो कुछ किया वह हमारे राष्ट्र के हित में है। पृथककरण की हमारी वचनबद्धता और हमारी सभी वचनबद्धताएं पारस्परिक हैं। जब तक अमेरिका की ओर से अपने वचनों को नहीं निभाया जायेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वे वचन क्या हैं? अमेरिका ने बहुत बड़े वचन दिए हैं। अनेक अपने राष्ट्रपति के ही शब्दों में उन्होंने भारत को पूर्ण गैर सैन्य नाभिकीय सहयोग तथा वे सभी लाभ देने का वचन दिया है जिनका आज नाभिकीय ऊर्जा वाले देश लुत्फ उठा रहे हैं। इसलिए, उनका वक्तव्य मूर्त रूप लेता है तो मैं सोचता हूं कि हमारे देश की गैर सैन्य नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि में नये युग का सूत्रपात होगा। मेरी अपनी दूरदृष्टि यह है कि अगले 15-20 वर्षों में हमें 30,000-40,000 मेगावाट नाभिकीय क्षमता में वृद्धि करनी होगी। मेरी दूरदृष्टि यह है कि इससे उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये मार्ग खुलेंगे। आज हमारे पास भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, लार्सन एण्ड टुब्रो जैसी उच्च प्रौद्योगिकी वाली कुछेक ही फर्में हैं। यदि हमारे पास वृहद नाभिकीय कार्यक्रम और अनुषंगी सुविधाएं होंगी तो इससे बहुत सी उच्च प्रौद्योगिकी फर्मों को बढ़ावा मिलेगा जिससे हम सामाजिक-आर्थिक विकास की दौड़ में ऊंची छलांग लगा सकेंगे। पृथकीकरण व्यवहार्य है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और हमारे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान इससे सहमत है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह पृथकीकरण थोपा नहीं गया है। इस पृथकीकरण का निर्णय हमारे स्वयं के निर्णय के आधार पर ही स्वैच्छिक रूप से लिया जायेगा। कोई भी बाह्य शक्ति यह नहीं कह सकती: "कि यह गैर सैन्य प्रतिष्ठान है और यह नाभिकीय प्रतिष्ठान है।" इसका निर्णय भारतीय जनता, हमारी सरकार और हमारे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों द्वारा किया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

इसके अलावा, पहचान की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप में होगी। मैं जानता हूं कि यह कार्य एक ही बार में नहीं हो सकता। यदि हमें अपने कार्यक्रम के गैर सैन्य और सैन्य घटकों को पृथक करना पड़ेगा तो इसमें समय लगेगा। और इसीलिए हमने आश्वासन दिया है कि यह पूर्णतः स्वैच्छिक निर्णय होगा, दूसरे यह चरणबद्ध कार्यक्रम होगा, महोदय, यह इतना चरणबद्ध होगा कि हमारे सामरिक कार्यक्रम का पूरा ध्यान रखा जायेगा। मैं यह आश्वासन देता हूं। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे भारत की सामरिक नाभिकीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में हमारी सामरिक स्वायत्तता के लिए कोई समझौता करना पड़े।

अटल जी ने भी फिसाइल मैटीरियल प्रोडक्शन कट-ऑफ संधि वार्ता के बारे में प्रश्न पूछा था। इस मामले में, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने पिछली सरकार द्वारा दिए गए वचनों के अलावा कोई अन्य वचन नहीं दिया है। और हमारा वचन क्या है? हमने

यह कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक बहुपक्षीय समझौते की वार्ता के अनुसार कार्य करेंगे। यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता नहीं है। इस समझौते पर जिनेवा में होने वाले नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्ता की जायेगी। कई वर्ष बीत चुके हैं जब इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। शीघ्र ही कोई समझौता नहीं होने वाला है। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा और किसी स्थिति में यदि निर्णय लेने की नौबत आ भी जाती है तो हम भेदभाव की नीति का शिकार नहीं होंगे। इसलिए, यदि नाभिकीय शक्तियां अपने अधिकारों की बात करेंगी तो हम भी उन्हीं अधिकारों के लिए जोर देंगे। इस प्रकार, बहुपक्षीय संधि की वार्ता के अनुसार अमेरिका के साथ सिर्फ कार्य करने के लिए सहमत होने से हमने अपने सामरिक परिसम्पत्ति कार्यक्रम की प्रभावशीलता को आत्मसमर्पित नहीं किया है।

महोदय, मैं इस सभा को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हम तीन ईंधन चक्रों पहला प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर; दो फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम और तीसरा थोरयिम आधारित रिएक्टर पर कार्य कर रहे हैं। हम अपने अनुसंधान कार्यक्रम को गैर सैन्य और नाभिकीय कार्यक्रम के पृथकीकरण की प्रक्रिया में किसी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देंगे। इस प्रकार, हमारे अनुसंधान वैज्ञानिक पूर्णत: आश्वस्त रहेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान प्रोत्साहन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की अनुसंधान क्षमता किसी भी स्थिति में प्रभावित हों। मैं भारत सरकार की ओर से यह वचन देता हूं।

अटल जी ने यह पूछा था कि हमें नाभिकीय शक्ति राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया। श्री फर्नांडीज ने भी यह प्रश्न पूछा था। यह सच है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्र वे हैं जिनकी एन.पी.टी. संधि के अंतर्गत पहचान की गई है। हमने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। हमें इसका सामना करना पड़ेगा। इस संधि को रातोंरात नहीं बदला जा सकता है। अमेरिका से हमें आभास मिला है कि हमें विधिक तौर पर नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा मिले बिना ऐसे राष्ट्रों के सभी लाभ प्राप्त होंगे।

सायं 7.00 बजे

मेरे विचार में यह हमारे लिए सुविधाजनक है। इस प्रकार यह तथ्य कि हमें विधिक तौर पर नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है, यह मेरी कार्यसूची में भी नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को रातों रात पुन: नहीं लिखा जा सकता है। किन्तु अब हमें अमेरिका ने यह वचन दिया है कि न केवल वह अपने प्रतिबंधात्मक शासन को हटा लेगा अपितु अपने गुट और मित्र देशों को भी ऐसा करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा इनकी वजह से भारतीय गैर सैन्य नाभिकीय कार्यक्रम का विकास बाधित होता रहा है। यह बात मेरे विभाग में स्पष्ट थी कि अमेरिकी कांग्रेस में अनिश्चितताएं हो सकती हैं। यद्यपि राष्ट्रपति बहुत उदार थे और उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को हमारी इच्छानुसार कानून बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे किन्तु यह अनिश्चित ही है। कांग्रेस क्या करेगी मैं इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता हूं। इसलिए, मैंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका न केवल अपने घरेलू कानूनों में संशोधन का वचन दे अपितु अपने गुट मित्रों और समर्थकों को भी अपने प्रभाव से इसके लिए तैयार करें। यदि अमेरिका की कांग्रेस इसे पारित नहीं करती है तो मैं सोचता हूं अमेरिकी सरकार का वचन भी अपने आप में कुछ अर्थ रखता हो।

हमें अपने नाभिकीय संयंत्रों के लिए और अधिक यूरेनियम की आवश्यकता है। हम अन्य देशों में भी गए थे और प्रत्येक ने इसके लिए 'हां' कर दी, उन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की किन्तु हमें इसके लिए अमेरिका को सहमत करना होगा। अब अमेरिका तैयार हो गया है, मेरे विचार से हमारे रिएक्टरों की ईंधन समस्या अब अतीत की बात हो जायेगी। मुझे इसकी पूरी आशा है। इस प्रकार, संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से कुछ न कुछ ठोस बात अवश्य प्राप्त हुई है। अटल जी ने यह प्रश्न भी पूछा था। हमें नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। हमें केवल उन्नत नाभिकीय प्रौद्योगिकी सम्पन्न नाभिकीय शक्ति माना जाता है किन्तु ब्राजील और अन्य कुछ देश भी ऐसे ही हैं। क्या हमें भी ब्राजील की तरह समझा जायेगा? मेरे विचार से यदि आपने वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें उससे बेहतर दर्जा मिल रहा है। हमें अमेरिका से स्पष्ट वचन मिला है कि भारत को अमेरिका जैसे उन्नत देश की तरह गैर सैन्य सहयोग के समान लाभ प्राप्त होने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इससे उपलब्ध अवसरों तथा संभावनाओं का स्वयं ही प्रभावी उत्तर मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मैंने अपने वामपंथी सहयोगियों तथा प्रमुख विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों दोनों की टिप्पणियों को सुना है। कृषि की भूमिका के बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए थे। महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी तरह सजग था। वस्तुत: वाशिंगटन जाने से पहले मैंने अधिकारियों से पहली बात यही पूछी थी कि "हम अपने देश में खाद्य सुरक्षा तथा कृषि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमरीका के साथ संयुक्त रूप से क्या कर सकते हैं?" तब मुझे पता चला कि हमारे देश में कृषि अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालयों, विस्तार कार्यों का स्तर ठीक नहीं है। ढींडसा साहब ने पंजाब की कृषि का हवाला दिया। जब सरदार प्रताप सिंह कैरों मुख्य मंत्री थे, तब मैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए मैं जानता हूं कि पंतनगर अथवा लुधियाना जैसे प्रथम श्रेणी के कृषि

[डा. मनमोहन सिंह]

विश्वविद्यालयों के उद्भव में भारत-अमरीका सहयोग ने क्या भूमिका निभाई है। परन्तु हमें यह मानना होगा कि इनमें से बहुत से विश्वविद्यालयों में अब अनुसंधान कार्य रुक सा गया है। मुझे लगता है कि कृषि में जानकारी की पहल के माध्यम से हम अनुसंधान सहयोग के एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं और मुझे आशा है कि इससे हम सभी प्रकार के विज्ञानों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा इसका हमारी कृषि समृद्धता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

इस संयुक्त वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि हम अपनी सीमाएं अमरीकी वस्तुओं के असीमित आगम के लिए खोल देंगे। इन मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ में अलग से विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति बुश के साथ बातचीत में इन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। यह बात अध्यक्ष महोदय मुझे रोज याद दिलाती हैं। हमारी प्रथम प्रतिबद्धता है-भारत के छोटे और मझोले किसान, जिन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। अपने किसानों की आजीविका रणनीतियों का संरक्षण करना हमारी सबसे बड़ी चिंता है और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि भारत के किसानों की आजीविका सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़े।

महोदय, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। यह बिल्कुल सही है कि इस मुद्दे पर अमरीका का बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। वे हमारे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहां जाने से पहले ही मुझे यह मालूम था। मैंने राष्ट्रपति बुश के साथ यह मामला उठाया और अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में भी यह मामला उठाया और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बात पर मुझे अमरीकी सदन कांग्रेस और सीनेट के सदस्यों की करतल ध्वनि सुनाई दी। मैं यह बताना नहीं चाहता कि राष्ट्रपति ने मुझसे क्या कहा परन्तु मैंने आशा नहीं छोड़ी है कि अंततः जब कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी तो भारत के दावों की अनदेखी नहीं की जाएगी। इस संयुक्त वक्तव्य में आपके पास स्वयं राष्ट्रपति का एक वक्तव्य होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को भारत की बढ़ती शक्ति के प्रति स्वयं को ढालना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं और मेरा यह दावा करना गलत होगा कि हमें अमरीका का समर्थन प्राप्त है परन्तु मेरा ऐसा मानने के कारण हैं कि जब समय आएगा तो भारत के दावे की अनदेखी नहीं की जा सकेगी।

अन्य प्रश्न जो उठाया गया था वह था-ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन का मुद्दा। महोदय, इस मुद्दे पर मैं बहुत स्पष्ट रहा हूं। जब मैं वाशिंगटन जा रहा था तो हमारे संवाददाताओं ने यह प्रश्न पूछा था और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह मामला हमारे पाकिस्तान और ईरान के बीच का है, अमरीका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मेरी बातचीत में यह प्रश्न कहीं नहीं उठा और न ही मैंने अमरीका में किसी से यह वादा किया कि हम इस परियोजना को वास्तविकता में नहीं बदलेंगे। जब वाशिंगटन पोस्ट के संपादकीय बोर्ड ने मेरा साक्षात्कार लिया तो उन्होंने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि "एक ओर तो आप परमाणु ऊर्जा चाहते हो, आप इस गैस पाइपलाइन की भी मांग कर रहे हो, आपको इन दोनों की आवश्यकता क्यों है?" इस पर मैंने कहा था "इस गैस पाइपलाइन के बारे में अनिश्चितता है। हम अभी तक प्रारंभिक चरण में हैं।" परन्तु मैंने कहा था "हमें गैस की बहुत आवश्यकता है।" सभा को मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार गैस पाइपलाइन को एक वास्तविकता में बदलने के प्रति वचनबद्ध है। परन्तु मेरा यह कहना गलत होगा कि यह कार्य पूरा हो चुका है। अभी समस्याएं हैं; हमें व्यवहार्यता को भी देखना होगा; हमें इनके वित्तपोषण के बारे में सोचना है। हम इन मुद्दों को सुलझाने के गंभीर प्रयास करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब में, मैंने कहा कि ईरान के साथ हमारे सभ्यतागत संबंध हैं और मैंने कहा कि हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा शिया समुदाय है और हम ईरान तथा अन्य देश के बीच विभिन्न मतभेदों को सुलझाने में एक सेतु होने का दावा कर सकते हैं। मैं एक पिछलग्गू राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं वहां भारत को बेचने नहीं गया था। मैंने इस सम्माननीय सभा द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय नीतियों का ही पालन किया है और महोदय मेरा मानना है कि मैंने कुल मिलाकर मुझे मिले जनादेश का पालन किया है।

महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह पूरी तरह प्रधान मंत्री पर निर्भर करता है कि वह इसका उत्तर दे या न दे। मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने चर्चा में भाग लेते हुए कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख किया था। फिलहाल मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैंने भारत-अमरीका द्विपक्षीय लोकतंत्र पहल के बारे में पूछा था। इस मुद्दे पर राष्ट्र स्पष्टीकरण चाहता है और माननीय प्रधान मंत्री इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, मैं डा. रूपचन्द पाल का आभारी हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि यह मामला प्रेस में भी उठाया गया और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इस स्थिति को स्पष्ट करने का मौका मिला है।

महोदय, यह सही है कि भारत के प्रति न केवल अमरीका में बल्कि विश्व के सभी देशों में अपार समर्थन और सम्मान है क्योंकि हमारे यहां पर कार्यशील लोकतंत्र है मैं जहां भी गया चाहे वह कांग्रेस हो या सीनेट की विदेश संबंध समिति हो या हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव इंटरनेशनल रिलेशन्स कमिटी, लोगों ने इस बात के लिए हमारी प्रशंसा की कि हमारे यहां पर अनेक प्रकार की जटिलताओं और विभिन्नताओं के होते हुए भी कार्यशील लोकतंत्र है। हम किस बात के लिए सहमत हुए हैं? हम इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि अमरीका और भारत अपने-अपने क्षेत्रों में उन देशों की मदद करेंगे जो मदद चाहते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी बात को लादा नहीं जा रहा है, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम पर किसी भी देश के विरुद्ध किए जाने वाले आक्रामक कार्य में भागीदार बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है और हम ऐसे प्रश्न पर विचार करे, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पास अपने स्वयं के लिए आईटीईसी कार्यक्रम है। महोदय, हमारे निर्वाचन आयोग को विश्व में सभी जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यदि कोई देश हमसे अपने यहां चुनाव कराने, मतदाता पंजीयन और अपने यहां लेखा कार्यालय स्थापित करने के संबंध में सहायता मांगता है जिसमें हमें विशेषज्ञता प्राप्त है तो हम उन्हें सहायता देंगे। हमने केवल इस बात का वचन दिया है कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होने वाले संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 10 मिलियन डालर का छोटा सा अंशदान करेंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वह इसका उत्तर दे या न दें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, जब माननीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे तो इन्होंने हमारे देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में यूरेनियम आपूर्ति के बारे में कहा था। जैसाकि आप जानते हैं कि हमारे पास मेघालय और झारखंड राज्य में यूरेनियम का प्रचुर भंडार है। इसलिए हम अपने भंडार का सृजन कर सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ताकि हम यूरेनियम के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और अपने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को स्थापित कर सकें क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी पहले से ही मौजूद है।

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, हम वह सब कर रहे हैं। जो हम अपने संसाधनों के दोहन के लिए कर सकते हैं। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं मैं इन कठिनाइयों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें अपने संसाधनों के दोहन में कोई कोट कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने कल ही अपने राज्य मंत्री से कहा है कि झारखंड में कुछ कठिनाइयां हैं जिनके चलते हम संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि चाहे वह मेघालय हो या चाहे वह आंध्र प्रदेश हो या झारखंड हो हमारे पास जहां भी यूरेयिनम के संसाधन है वहां पर हम इन संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त वक्तव्य में हमारे परमाणु रिएक्टरों के लिए यू-37 की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। लेकिन अमरीका प्रभुत्ववादी नीति और अमरीकी नीति जिस बात पर जोर देती है, के संबंध में वे बदले में हमसे क्या चाहते हैं जैसाकि ऐसा कहा गया है कि यह पारस्परिक चीज है? क्या यह हृदय परिवर्तन है अथवा मात्र सद्भावना मिशन है और साझा बयान में इसका प्रादुर्भाव हुआ है?

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, मैं कह सकता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसका उल्लेख साझा बयान में नहीं किया गया है। कोई गुप्त वार्ता या गुप्त समझौता नहीं हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने लगभग वही कहा था जिस बात पर सहमति हुई थी? इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि मुझ पर लोगों के विचारों को भांपने का आरोप लगाया जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूं कि अमरीका सरकार ने इस बात को माना है कि यह उनके देश के हित में है कि एक अरब की आबादी वाले देश, एक कार्यशील लोकतंत्र का विकास करना चाहिए। हम न केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व में शांति, विकास और स्थिरता का एक कारक हो सकते हैं और होंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय मैं केवल दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली यदि मैंने उनकी बात ठीक से समझी है तो इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी कहा गया है यदि अमरीकी कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करती है तो भी अमरीकी सरकार इस पर कायम रहेगी। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं।

दूसरा, मैंने अपने भाषण में भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी और इन्होंने पुनः कहा था कि वर्तमान भारत निर्माण; शक्तिशाली भारत निर्माण की प्रक्रिया 1947 में ही आरंभ होकर 1991 में समाप्त हो गई थी। क्या 1991 से 2004 के बीच कुछ नहीं हुआ?

डा. मनमोहन सिंह: महोदय यह वह प्रकल्पना नहीं है जो मैं चाहता हूं कि वह मानें। मैं सोचता हूं कि एक देश होने के नाते हमारा प्रयास देश के सतत विकास के साथ परिवर्तन का

[डा. मनमोहन सिंह]

संतुलन बिठाना है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हुआ है वह जो कुछ मैंने किया है अथवा हमारी सरकारों ने किया है। लेकिन पंडित जी, इंदिरा जी और राजीव जी के योगदान से कौन इन्कार कर सकता है? मैं यह भी कहता हूं कि एनडीए के शासनकाल में भी कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं। यह उचित नहीं है। वह चालीस मिनट तक बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है और इस पर 40 मिनट बोले हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या आप तात्कालिक महत्व के मामले उठाना चाहते हैं जिन पर शाम को चर्चा होती है?

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, लोनाप्पन नम्बाडन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नम्बाडन, आप अपने मामले का उल्लेख करें। क्या आपको याद है कि आपका विषय क्या है?

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): अध्यक्ष महोदय, मैं अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ईसाई समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न संबंधी मामले को सभा के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं और उन्हें उनके जानमाल को नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही हैं।

सायं 7.19 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

यह दर्शाने के लिए मैं कई उदाहरण दूंगा कि इन असामाजिक तत्वों ने पूरे देश में पादरियों एवं ननों पर हमले किए हैं और उन्हें जान से मारा है, जो ईसाई समुदाय के हैं। उड़ीसा में, हाल ही में एक पादरी को पीटने और उत्पीड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उड़ीसा में ही, दूसरे पादरी की उसके घर में ही हत्या कर दी गई थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र केरल में गत वर्ष, अगस्त, 2004 को फादर जॉब चितिलापिल्ली की हत्या कर दी गई थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र केरल में गत वर्ष, अगस्त, 2004 को फादर जॉब चितिलापिल्ली की हत्या कर दी गई थी। पुलिस हत्यारे को अब तक नहीं पकड़ सकी है। पटना, बिहार में एक वाइकर जनरल, फादर मैथ्यु की हत्या कर दी गई थी, इनके अलावा, कई शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, धर्मार्थ केन्द्रों और गिरजाघरों पर हमले हो रहे हैं और गुण्डों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें लूटा जा रहा है।

इससे अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के बीच असुरक्षा और घबराहट बढ़ती है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हो रहे इन उत्पीड़नों को रोकने एवं विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द भाव को बनाये रखने तथा उसे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष जी, पूरे देश में सावन के महीने में हरिद्वार से कांवड़ भरकर शिवभक्त कांवड़िये नीलकंठ, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर तथा विभिन्न मंदिरों में जल चढ़ाने जाते हैं। आपने उनकी समस्याओं को यहां पर रखने के लिए, मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। उनमें पांच वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के तमाम श्रद्धालु हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं और जो हरिद्वार से जल लेकर देश के विभिन्न मंदिरों में चढ़ाने और पूजा अर्चना करने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लाने वाला एक बालक लापता है। गाजियाबाद में सावन-शिवरात्रि मेले के अवसर पर कांवड़ियों की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा होनी चाहिए। यातायात के विषय में आपने अखबारों में भी देखा होगा कि कांवड़िये नेशनल हाई-वे तथा तमाम दूसरे मार्गों पर भी चल रहे हैं। उनके लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिससे उनका एक्सीडेंट न हो। मार्ग दुर्घटना में भी कई कांवड़िये मारे गये हैं, उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्था राज्य सरकार या केन्द्र सरकार करे। दूसरी तरफ ऐसे रास्ते हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, उन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कराई जाए और जहां सड़कें टूटी-फूटी हैं उनकी मरम्मत कराई जाए।

देश में ऐसे श्रद्धा के स्थान हैं चाहे शिरडी हो, नासिक हो, वाराणसी हो या उज्जैन में मांडेश्वर मंदिर हो या उत्तर प्रदेश में बाराबंकी हो, वहां तमाम श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं। वहां राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।